महत्वपूर्ण

संख्या-02/2015/293/31-2015-76/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2015

विषयः- उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2015-16

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में विकास के एजेण्डा को प्रदेश की जनता के सामने रखती है एवं विकास के एजेण्डा को क्रियान्वित करने के लिए पूरे वर्ष समयबद्ध रूप से कार्य किया जाता है। उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 निर्धारित किए गए थे जिन पर सुनियोजित तरीके से कार्य करने के फलस्वरूप उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा विकास एजेण्डा में शामिल कई बिन्दुओं पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी अनुक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करते हुए अल्प अवधि में इसका अधिकाधिक लाभ जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता वाले सूत्रों को चिन्हित करते हुए "उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2015-16" निर्धारित कर संलग्न किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कुल 165 एजेण्डा बिन्दु समाहित है, ताकि वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रारम्भ होते ही इसका कार्यान्वयन शुरू हो सके और इस हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में एजेण्डा बिन्दुओं की पूर्ति हेतु आवश्यक बजट प्राविधान किया जा सके।

2. प्रस्तावित एजेण्डा बिन्दुओं में एक ओर जहाँ प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए जाने के साथ-साथ भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके सही ढंग से लागू किया जाना सम्मिलित है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष लागू की गयी विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीति, निजी निवेश अर्जित करने का प्रयास, जन सामान्य के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन एवं ग्राम्य विकास सेक्टरों के विशिष्ट कार्य बिन्दुओं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम तथा प्रशासन तंत्र को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए जाने के लिए अभिनव प्रयास एवं नई योजनाएं भी सम्मिलित हैं।

3. उल्लेखनीय है कि विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 में समस्त विकास सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र होगा। विकास एजेण्डा के कार्यान्वयन का मासिक अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा यथासमय इस एजेण्डा का त्रैमासिक अनुश्रवण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इन एजेण्डा बिन्दुओं पर विभाग द्वारा अर्जित की गयी प्रगति को सम्बन्धित विभाग की उपलब्धियों के रूप में भी आंकलित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 हेतु अपने विभाग के चिन्हित एजेण्डा बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए एक से तीन वाक्य तक अपने विभाग का विजन स्टेटमेन्ट दिनांक 15 फरवरी, 2015 तक प्रत्येक दशा में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 हेतु अपने विभाग के चिन्हित एजेण्डा बिन्दुओं पर वार्षिक मात्रात्मक लक्ष्य दिनांक 15 मार्च, 2015 तक प्रत्येक दशा में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. आपसे यह अपेक्षा है कि अपने विभाग के समस्त एजेण्डा बिन्दुओं के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में आपके द्वारा ससमय आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किए जाएगें।

7. आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त एजेण्डा में अपने विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य बिन्दु के माइल स्टोन्स व उनकी पूर्ति हेतु समय सारिणी एवं अनुश्रवण हेतु प्रारूप विकसित करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ कर दें, ताकि इन बिन्दुओं का माह अप्रैल, 2015 से ही नियमित अनुश्रवण प्रारम्भ किया जा सके। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त एजेण्डा को अपनी विभागीय समीक्षा में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसके उद्देश्यों की पूर्ति समय-सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक- उत्तर प्रदेश के विकास हेतु
शासन का एजेण्डा, वर्ष 2015-16

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-02/2015/293(1)/31-2015-76/2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2015/293(2)/31-2015-76/2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
1	2	3
1	प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।	वित्त
कृषि क्षेत्र		
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।	कृषि
3	क- खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर (VRR) में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना। ख- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण के लिए मैकेनाइजेशन मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन।	कृषि
4	सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना किया जाना।	कृषि
5	पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।	कृषि
6	पश्चिमी उ0प्र0 में क्रॉप डाईवर्सीफिकेशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	समन्वय
7	क- कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब की स्थापना। ख- नवीन मण्डियों की स्थापना। ग- किसान बाजार का विकास।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
8	एकीकृत बागवानी विकास मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
9	क- उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
10	गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास तथा बीज उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाना, जिससे गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
11	उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
12	कामधेनु डेयरी इकाईयों की ब्याज-मुक्त ऋण योजना (100/50 गाय-भैंस) का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
13	मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाया जाना।	मत्स्य

http://shasanadesh.up.nic.in

उद्योग, अवस्थापना एवं लोक निर्माण क्षेत्र		
14	लखनऊ में 05 लाख लीटर, कानपुर में 10 लाख लीटर, वाराणसी में 05 लाख लीटर तथा इटावा में 05 लाख लीटर दैनिक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के डेरी प्लाण्ट स्थापित किया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
15	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
16	क- दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना (एडीकेआईसी) के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना तथा कॉरीडोर के आस-पास औद्योगिक तथा शहरी गतिविधिओं को विकसित करने हेतु योजना बनाया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
17	क- ट्रान्स गंगा परियोजना। ख- संगम सिटी का विकास।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
18	जनपद औरैया में प्लास्टिक सिटी परियोजना का कार्यान्वयन तथा उद्योगों की स्थापना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
19	नोएडा/ग्रेटर नोएडा में पार्कों की स्थापना किया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
20	नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, मथुरा, इटावा (सैफई) में साइकिल ट्रैक बनाया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/आवास
21	मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	लघु उद्योग
22	एम0एस0एम0ई0 पोर्टल विकसित किया जाना।	लघु उद्योग
23	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं एक्सपोर्ट नीति घोषित किया जाना।	लघु उद्योग
24	समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण
25	क-अधूरे नदी सेतुओं को पूर्ण किया जाना। ख-यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु चिन्हित स्थानों पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कराया जाना तथा अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण कराया जाना।	लोक निर्माण
26	उपशा द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर निर्मित कराई जा रही सड़कों का अनुश्रवण।	लोक निर्माण
27	प्रदेश में कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं चक्रानुसार शतप्रतिशत मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
28	लखनऊ में आई0टी0 सिटी की स्थापना किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
29	यमुना एक्सप्रेस वे तथा ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई0एम0सी0) का विकास किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स

http://shasanadesh.up.nic.in

30	कुशीनगर/ताज क्षेत्र, आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का रन-वे विकसित किया जाना।	पर्यटन
31	प्रो-पूअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट।	पर्यटन
32	हेरिटेज आर्क का पर्यटन विकास।	पर्यटन
33	पर्यटन आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेन्ट मैनेजमेण्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना।	पर्यटन
34	क- छतर मंजिल परिसर, लखनऊ का पर्यटन एवं सांस्कृतिक संकुल के रूप में विकास। ख- नव निर्मित राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज का आधुनिकीकरण करते हुए उसे बाल एवं सांइस म्यूजियम के रूप में विकास किया जाना।	संस्कृति
35	मैत्रेय परियोजना, कुशीनगर का प्रभावी कार्यान्वयन।	संस्कृति
36	व्यक्तिगत बुनकरों को क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जाना।	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
ऊर्जा क्षेत्र		
37	राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
38	वर्ष 2016-17 में जनपद मुख्यालय को न्यूनतम 22 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को न्यूनतम 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
39	ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
40	क- केस-2 बिडिंग के आधार पर प्रस्तावित करछना परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना। ख- प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु अनपरा-डी (2X500मे0वा0) की इकाईयों से उत्पादन प्रारम्भ करना। ग- हरदुआगंज में (1X660मे0वा0) इकाई की ई0पी0सी0 आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन। घ- मेजा एवं घाटमपुर में संयुक्त उपक्रम द्वारा बनायी जा रही तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाना। ड़- केस-2 बिडिंग के आधार पर निर्माणाधीन बारा परियोजना की दो इकाईयों से उत्पादन प्रारम्भ करना।	ऊर्जा
41	क- पी0पी0पी0 आधार पर चलायी जा रही इलाहाबाद-मैनपुरी एवं मैनपुरी-ग्रेटर नौएडा पारेषण परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना। ख- ललितपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु निर्माणाधीन पारेषण परियोजना का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कर उनके निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना।	ऊर्जा
42	प्रदेश के विद्युत गृहों के वित्तीय वर्ष 2015-16 में विगत वर्ष 2014-15 के	ऊर्जा

http://shasanadesh.up.nic.in

	सापेक्ष कम से कम 05 प्रतिशत पी0एल0एफ0 को बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाकर उसका समयबद्ध कार्यान्वयन कराया जाना।	
43	विद्युत वितरण के चिन्हित शहरी क्षेत्रों में निजी सहभागिता से समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (AT&C Losses) को कम किया जाना।	ऊर्जा
44	प्रदेश में हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग से जुड़े कस्बों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था कर बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
45	ग्रामीण क्षेत्रों में सैपरेट फीडर की प्रणाली को विकसित किया जाना।	ऊर्जा
46	क- उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- रूफटॉप सोलर पॉलिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
47	सोलर पार्क के विकास का प्रभावी कार्यान्वयन।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
48	क- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जाना, जिससे बत्ती-पंखा के साथ-साथ कुछ अन्य आवश्यक घरेलू उपकरण भी चल सकें। ख- ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक 8 स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
49	नेडा का सुदृढ़ीकरण किया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
50	चयनित ग्रामों में सौर ऊर्जा आधारित मिनी ग्रिड योजना को क्रियान्वित कराया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
मानव संसाधन विकास क्षेत्र		
51	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	उच्च शिक्षा
52	उच्च शिक्षण संस्थाओं की एन.ए.ए.सी से मूल्यांकन करा कर उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाना।	उच्च शिक्षा
53	"QS World University Ranking /Times Higher Education Ranking" के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 02 विश्वविद्यालयों को उनकी वर्तमान रैंकिंग से "50 रैंक" ऊपर के स्तर पर लाने का प्रयास किया जाना।	उच्च शिक्षा
54	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
55	मॉडल स्कूलों में बाउन्ड्रीवाल एवं बालिका छात्रावास निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
56	मा0 न्यायालयों में शिक्षा संबंधी वादों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
57	मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित पुर्नगठित कन्या विद्या धन योजना।	माध्यमिक शिक्षा
58	प्रदेश में 10 नये इण्टर कालेज स्थापित किया जाना, जिनके लिये एक मुश्त धनराशि बजट में प्राविधानित रहेगी।	माध्यमिक शिक्षा
59	सर्व शिक्षा अभियान।	बेसिक शिक्षा
60	कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यायल में कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं प्रारम्भ कराना तथा छात्रावासों का निर्माण किया जाना।	बेसिक शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

61	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा
62	कौशल विकास मिशन।	व्यावसायिक शिक्षा
63	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण क्षमता का मांग परक विस्तार किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
64	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को पूर्ण क्षमता से क्रियाशील किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
65	लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किया जाना तथा शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षाएं प्रारम्भ कराया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
66	क- बॉदा, बिजनौर एवं अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद के निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेजों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना। ख- बॉदा, बिजनौर एवं अम्बेडकर नगर के इंजीनियरिंग कालेजों में शैक्षिक सत्र 2015-16 से नवनिर्मित भवनों में तथा मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र इंजीनियरिंग कालेज की कक्षाएं अन्य राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में संचालित कराया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
67	हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
68	प्रदेश के शासकीय/निजी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया तथा उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में कॉलेजों की सम्बद्धता को सरल बनाते हुए इसकी ऑन -लाइन व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2015-16 से प्रारम्भ किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
69	उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के नोएडा कैम्पस में इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन की स्थापना किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
70	ट्रांसगंगा क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा विभाग से समन्वय कर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
71	प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर में संचालित कृषि महाविद्यालय का एक्रेडिटेशन (प्रयोगशाला सहित) आई0सी0ए0आर0 से कराया जाना।	कृषि शिक्षा
72	क-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना किया जाना। ख-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना किया जाना।	कृषि शिक्षा
73	प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए लैब्रोटरी एवं आनलाईन जरनल की व्यवस्था किया जाना ताकि छात्रों एवं	चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

	अध्यापकों को रिसर्च करने की सुविधा प्राप्त हो सकें।	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र		
74	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
75	वर्ष 2012 से पूर्व एवं वर्ष 2012 के पश्चात निर्माणाधीन जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
76	क- चिन्हित 50 महिला चिकित्सालयों में 100 बेड मैटरनिटी विंग का निर्माण किया जाना। ख- चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 बेड मैटरनिटी विंग का निर्माण किया जाना। ग- लखनऊ तथा 05 अन्य चिन्हित जनपदों में 200 बेड के मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों का निर्माण किया जाना। घ- निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए वेब आधारित प्रणाली को विकसित किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
77	निजी सहभागिता से चक गंजरिया में सुपर स्पेशियलटी अस्पताल की स्थापना, ट्रामा सेंटर की स्थापना एवं क्रियाशीलता, रीजनल डायगनोस्टिक सेंटर की प्रगति तथा हीमोडायलसिस सेंटर की स्थापना किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
78	ट्रामा सेंटर एवं ट्रामा विंग का निर्माण किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
79	स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख इंडिकेटरों में सुधार लानाः- क- संस्थागत प्रसव में 10 प्रतिशत की वृद्धि। ख- पूर्ण प्रतिरक्षण में 10 प्रतिशत की वृद्धि। ग- आधुनिक गर्भ निरोधक तकनीकों/विधियों के प्रयोग में 10 प्रतिशत की वृद्धि।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
80	Uttar pradesh Drugs & Pharmaceuticals Co. Ltd. का आधुनिकीकरण कर इस तरह विकसित किया जाना जिससे वह स्वयं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों को दवायें सप्लायी कर सकें।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
81	एड्स पीड़ित बच्चों के देख-भाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
82	प्रदेश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थात्मक सुधार किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
83	प्रत्येक जनपद में आधुनिक मर्चुरी/पोस्टमार्टम हाउसेस का निर्माण किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
84	जिला अस्पतालों में जहॉ बर्न यूनिट्स नहीं है, वहॉ भवन की स्थापना किया	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

	जाना।	परिवार कल्याण
85	राज्य पोषण मिशन।	बाल विकास एवं पुष्टाहार
86	क- कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना किया जाना। ख- राज्य कैंसर संस्थान, कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद का निर्माण कर उसे क्रियाशील किया जाना। ग- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ; मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं मेडिकल कालेज,झांसी में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र विकसित किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
87	क- ग्रेटर नोएडा में सुपर-स्पेशियलटी अस्पताल से युक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना। ख- सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
88	डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ एवं डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट, लखनऊ को आपस में विलय करते हुए एक संयुक्त चिकित्सा संस्थान की स्थापना किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
89	भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश स्तर के आयुष मिशन संचालित किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
90	प्रदेश में पैरामेडिकल शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं विनियमित करते हुए इस क्षेत्र में कौशलयुक्त/प्रशिक्षित प्रोफेशनल का सृजन।	चिकित्सा शिक्षा
91	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं में सुदृढ़ीकरण, प्रयोगशालाओं का एन0ए0बी0एल0 एक्रेडिटेशन एवं जनसामान्य को खाद्य पदार्थों की विश्लेषण सुविधा प्रदान किया जाना।	खाद्य एवं औषधि प्रशासन
सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम क्षेत्र		
92	समाजवादी पेंशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	समाज कल्याण
93	उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के अंतर्गत प्रदेश के 25 और जनपदों में निर्धन वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रमों का संचालन कराया जाना।	समाज कल्याण
94	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किया जाना।	समाज कल्याण
95	मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम।	अल्पसंख्यक कल्याण
96	प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक हब की स्थापना किया जाना।	अल्पसंख्यक कल्याण
97	राजकीय कार्यालयों, संस्थानों एवं नगरीय निकायो के भवनों को डिसेबेल्ड फ्रेन्डली बनाया जाना।	विकलांग कल्याण
98	क- रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना किया जाना। ख- रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार।	महिला कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

	ग- रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना किया जाना।	
99	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना।	खाद्य एवं रसद
100	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	खाद्य एवं रसद
101	राज्य खाद्यान्न भण्डारण नीति का निर्धारण कर भण्डारण क्षमता सृजित किया जाना।	खाद्य एवं रसद
102	क- कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
103	श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण/लाइसेन्सिंग की प्रक्रिया को जनहित में त्वरित गति प्रदान किए जाने हेतु ऑनलाइन किया जाना।	श्रम
104	सेस के लक्ष्य को क्षमता के अनुरूप बढ़ाकर संग्रहीत किया जाना तथा उपयुक्त योजनाएं बनाकर श्रमिकों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाना।	श्रम
105	श्रम कानूनो में सुधार/सरलीकरण किया जाना।	श्रम
106	प्रदेश के बेरोजगारों के लिए इम्प्लायमेन्ट पोर्टल।	श्रम
ग्राम विकास क्षेत्र		
107	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।	समग्र ग्राम विकास
108	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''प्रेरणा''।	ग्राम्य विकास
109	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।	ग्राम्य विकास
110	क- लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ख- इन्दिरा आवास योजना।	ग्राम्य विकास
111	प्रदेश के ब्लॉकों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	ग्राम्य विकास
112	सौर ऊर्जा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप पेयजल की व्यवस्था किया जाना।	ग्राम्य विकास
113	प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारियो को ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टेबलेट दिया जाना।	ग्राम्य विकास
114	State Clean and Green Mission बनाकर लागू किया जाना।	पंचायतीराज
115	प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टेबलेट दिया जाना।	पंचायतीराज
116	जनेश्वर मिश्र ग्राम्य योजना।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
नगर विकास एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन क्षेत्र		
117	क- लखनऊ हाट (अवध शिल्प ग्राम योजना) की स्थापना किया जाना। ख- लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण किया जाना। ग- लखनऊ में जय प्रकाश नारायण इण्टरनेशनल कन्वैन्शन सेन्टर का निर्माण किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

	ध- लखनऊ में अन्तराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीडा संकुल का निर्माण किया जाना। ङ- गोमती नगर, लखनऊ में अंडरपास का निर्माण किया जाना। च-लखनऊ के अधूरे आर0ओ0बी0/फ्लाई ओवर्स को पूर्ण कराया जाना।	
118	लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
119	चक गंजरिया फार्म की भूमि पर सी.जी. सिटी तथा अन्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
120	इनर रिंग रोड, आगरा का निर्माण किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
121	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
122	इटावा स्पिनिंग मिल परिसर का आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुनियोजित विकास किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
123	कतिपय महानगरों में सड़कों पर रहने वाले निराश्रितों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
124	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. घटकों सहित) के अवशेष कार्यों को पूर्ण किया जाना।	नगर विकास
125	नेशनल गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना।	नगर विकास
126	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगर विकास
127	सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव के नाम से पार्क की स्थापना किया जाना।	नगर विकास
128	क- राजीव आवास योजना। ख- शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
129	रिक्शा चालकों के हित के लिए बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
130	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
131	लखनऊ में गोमती नदी, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी तथा वाराणसी में वरूणा नदी का तटीय विकास किया जाना।	सिंचाई एवं जल संसाधन
पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन		
132	जनोपयोगी व्यवस्थाओं का पी0पी0पी0 आधार पर समग्र आधुनिकीकरण किया जाना।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजि0)
133	क- शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने	सचिवालय प्रशासन

http://shasanadesh.up.nic.in

	की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं अनुश्रवण किया जाना। ख- सचिवालय में व्यवहृत की जाने वाली पत्रावलियों पर बार-कोडिंग करते हुए फाइल-ट्रैकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जाना। ग- उ0प्र0 सचिवालय के अनुभागों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों/अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कराया जाना।	
134	क- जनोपयोगी विभागों में रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरा जाना। ख- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना। ग- प्रदेश में उर्दू अध्यापकों एवं उर्दू अनुवादकों की भर्ती किया जाना।	कार्मिक एवं नियुक्ति
135	प्रदेश की तहसीलों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	राजस्व
136	प्रदेश के समस्त लेखपालों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टेबलेट दिया जाना।	राजस्व
137	क- राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना। ख- भू-मानचित्र (शजरा) का डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटराइजेशन किया जाना।	राजस्व
138	नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में सभी विभागों के पदों का सृजन एवं तैनाती तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना।	राजस्व
139	राजस्व वादों का शीघ्र निस्तारण/कमी लाने के लिए विभिन्न राजस्व विधि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना।	राजस्व
140	प्रदेश में पुलिस के रिक्त पड़े उपनिरीक्षकों एवं आरक्षी के पदों के सापेक्ष 4000 (चार हजार) उपनिरीक्षक तथा 40000 (चालीस हजार) आरक्षी की भर्ती की कार्यवाही किया जाना।	गृह
141	सी0सी0टी0एन0एस0 योजना को पूर्ण रूप से प्रदेश के सभी थानों में क्रियाशील किया जाना।	गृह
142	प्रदेश के 12 जनपदों में एकीकृत यातायात प्रबन्धन व्यवस्था लागू किया जाना।	गृह
143	प्रदेश व्यापी डायल 100 सेवा की स्थापना/सुदृढीकरण किया जाना।	गृह
144	प्रदेश के थानों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	गृह
145	ग्राम चैकीदारों के रिक्त पदों को भरा जाना।	गृह
146	एक सेन्ट्रलाईज मेगा काल सेन्टर बनाया जाना जो विभिन्न लाभार्थियों से योजनाओं के बारे में स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करेगा।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
147	प्रदेश के समस्त लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टेबलेट दिए जाने की गाइड-लाइन्स निष्पादित किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
148	जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अधिकतम शासकीय सेवाएं प्रदान किया	सूचना प्रौद्योगिकी एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

	जाना एवं उन सेवाओं को ऑन-लाइन उपलब्ध कराया जाना।	इलैक्ट्रानिक्स
149	Integrated grievance redressal system बनाया जाना।	लोक शिकायत
150	एक इनोवेशन सेल और स्टेट इनोवेशन फण्ड की स्थापना कर प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न नये विचारों को सहयोग देना तथा उन्हें आगे बढ़ने हेतु रिप्लीकेट कराना।	नियोजन
151	एन0जी0ओ0 के साथ सहभागिता के लिए प्रोसीजर्स तय किया जाना।	नियोजन
152	जनसमुदाय/हित धारकों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता जॉचने हेतु स्वतंत्र एजेन्सियों का पैनल बनाया जाना।	नियोजन
153	आधार कार्ड हेतु नामांकन तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन तथा आधार कार्ड के साथ लिंकेज का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	नियोजन
154	विभिन्न विभागों की 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति प्राप्त अवस्थापनाओं का ई-अनुश्रवण करते हुए इन्हें पूर्ण किया जाना तथा इन सभी तथा पूर्व निर्मित भौतिक अवस्थापनाओं को जनोपयोगी बनाया जाना।	नियोजन
155	सरकारी विभागों के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या कम करने हेतु प्रदेश में विद्यमान मुकदमा नीति में यथावश्यक संशोधन कर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना।	न्याय
अन्य कार्यक्रम		
156	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं।	समस्त विभाग
157	जैव प्रौद्योगिकी नीति-2014 का निर्धारण एवं नीति के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश का विकास किया जाना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
158	बड़े शहरों में रेडियो टैक्सी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	परिवहन
159	प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू किया जाना।	परिवहन
160	सड़क सुरक्षा नीति का परिवहन, गृह, लोक निर्माण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना।	परिवहन
161	क- इटावा में लायन सफारी विकास किया जाना। ख- इटावा में सफारी पार्क्स का विकास किया जाना।	वन
162	प्रत्येक जनपद में विभिन्न स्थानों पर हरित पट्टी का विकास करके कुल 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना।	वन
163	राजीव गांधी खेल अभियान।	युवा कल्याण
164	अन्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती हेतु नीति बनाया जाना।	खेल
165	बुन्देलखण्ड पैकेज का प्रभावी कार्यान्वयन।	नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in